भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1652

27 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

शुद्ध शून्य उत्सर्जन

1652. श्री अब्दुल खालेक:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस हेतु जल्द ही कोई नई योजना शुरू की जानी है;

(ग) क्या सरकार असम में संवहनीय परियोजनाओं के लिए निधि उपलब्ध कराएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाएगा?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) और (ख): जी, हाँ। निवल शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:

(i) स्वदेशी रूप से उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना। स्क्रैप रूट से इस्पात का उत्पादन करने से अपेक्षाकृत कम प्रदूषण होता है।

(ii) इस्पात उद्योग के अकार्बनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग संघों और स्वदेशी इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सहभागिता।

(iii) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास और विस्तार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन स्थापित करने की घोषणा की है। इस मिशन में इस्पात क्षेत्र को भी हितधारक बनाया गया है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) सरकार ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की है।

*****